निवेश नीतियों की नियमावली हुई जारी

निवेशकों की सुविधा के लिए बनाई गई 25 सेक्टोरल नीतियां हुई अधिसूचित

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लागू 25 सेक्टर की औद्योगिक निवेश नीतियों की नियमावली आखिरकार जारी हो गई है। अमर उजाला ने 12 अप्रैल के संस्करण में नीतियां बन गईं, लेकिन बिना नियमावली कैसे होगा निवेश शीर्षक से प्रकाशित खबर में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।

इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त कार्यालय तक हरकत में आए। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बृहस्पतिवार को पिकअप भवन स्थित सभागार में 25 सेक्टरोल निवेश नीतियों की नियमावली, प्रक्रिया और नियम शर्तें जारी होने की समीक्षा की। बैठक में नंदी को बताया गया कि अब सभी निवेश नीतियों की नियमावली जारी कर नीति को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके बाद निवेशकों को उद्योग स्थापित करने और निवेश नीति के तहत प्रोत्साहन व रियायतें प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नीतियां तो बन गईं, लेकिन बिना नियमावली कैसे होगा निवेश

अमर उजाला ने 12 अप्रैल को प्रकाशित खबर 'नीतियां बन गईं, लेकिन बिना नियमावली कैसे होगा निवेश' के जरिए उठाया था मामला।

नंदी ने बैठक में शासन की नीतियों में किए जा रहे आवश्यक परिवर्तन के संबंध में विभागों की ओर से जारी किए जा रहे शासनादेशों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इसमें अधिकारियों ने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों की ओर से जो 25 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई गई हैं, वे सभी संबंधित विभागों की ओर से नोटिफाई कर दी गई हैं। निवेशकों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया कि नियमावली जारी हो गई हैं।

पहले भूमि पूजन के लिए 20,293 करोड़ की 519 परियोजनाओं के शिलान्यास को मिली मंजूरी

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 के बाद अगस्त-सितंबर में होने वाले पहले भूमि पूजन के लिए 20,293 करोड़ रुपये की 519 परियोजनाओं के शिलान्यास की मंजूरी दे दी गई है। पिकअप भवन में बृहस्पतिवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

नंदी ने बैठक में कहा कि निवेशकों को सहूलियत सरकार की प्राथमिकता है। आईटी, आईटीएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई के साथ ही अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवेशक निवेश को तैयार हैं और आगे आ रहे हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एमओयू क्रियान्वयन एवं विभागों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी में आठ सपोर्ट यूनिट का गठन किया गया है। सभी 35 विभागों के अधिकारी निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी तक 371 निवेशकों से संपर्क किया गया है। जिन एमओयू को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सकता है, उसके लिए कई निवेशकों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया कि पहले भूमि पूजन समारोह के लिए लक्ष्य की तुलना में प्रत्येक विभाग की प्रगति की अलग से निगरानी की जा रही है। निवेश सारथी पर भूमि पूजन के लिए चिह्नित परियोजनाओं और उनकी स्थिति जानने के लिए विभागों को सुविधा ऑनलाइन की गई है। ब्यूरो

सितंबर-अगस्त में प्रस्तावित भूमि पूजन में दस लाख करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास का लक्ष्य

विभाग	स्वीकृत परियोजनाएं	निवेश राशि (करोड़ में)
यूपीसीडा	51	8578
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	18	39,875
नोएडा अथॉरिटी	59	40,617
उच्च शिक्षा	27	10,225
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी	109	69,970
उद्यानिकी विभाग	76	2213
यीडा	15	23,027
पर्यटन	246	15,336
वन विभाग	07	3755
कौशल विकास	01	4174